

## भाषाई अंतर को पाटना: भारत में बहुभाषी शिक्षा की अनिवार्यता

### यूपीएससी प्रासंगिकता

- **GS पेपर I:** भारतीय समाज (भारत की विविधता)।
- **GS पेपर II:** सामाजिक न्याय (शिक्षा और मानव संसाधन); शासन।
- **GS पेपर IV:** नीतिशास्त्र (विविधता और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान)।

### चर्चा में क्यों? (Why in the News?)

- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फरवरी, 2026) के अवसर पर, यूनेस्को (UNESCO) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट का 7वां संस्करण जारी किया।
- इस रिपोर्ट का शीर्षक है "भाषा मैटर्स: मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा।"
- यह रिपोर्ट भारत के सीखने के संकट को दूर करने में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (MTB-MLE) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।



### पृष्ठभूमि: भारत की बहुभाषी वास्तविकता (Background)

- भारत 1,300 से अधिक मातृभाषाओं और 121 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं के साथ एक भाषाई शक्ति केंद्र है।
- हालाँकि, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी "भाषा की बाधा" मौजूद है।
- NCERT (2022) के अनुसार, लगभग 44% भारतीय बच्चे ऐसी भाषा बोलने वाले स्कूलों में प्रवेश करते हैं जो उनके शिक्षा के माध्यम से अलग होती है।

### इस भाषाई बेमेल के कारण अक्सर ये समस्याएं होती हैं:

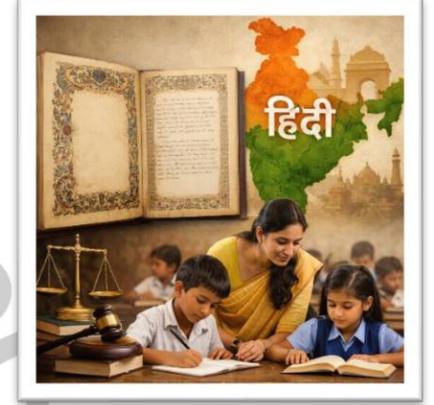
- **संज्ञानात्मक बोझ (Cognitive Burden):** बच्चे शैक्षणिक अवधारणाओं को सीखने के साथ-साथ एक नई भाषा को समझने के लिए संघर्ष करते हैं।
- **सीखने का अंतर (Learning Gaps):** बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) कौशल का कमजोर होना।

- **सामाजिक बहिष्कार (Social Exclusion):** स्कूल छोड़ने की उच्च दर, विशेष रूप से आदिवासी और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों में।

## I. बहु-आयामी दृष्टिकोण (Multi-Dimensional Perspectives)

### 1. संवैधानिक और कानूनी ढांचा (Constitutional & Legal Framework)

- **अनुच्छेद 350A:** हर राज्य को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में निर्देश के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का आदेश देता है।
- **अनुच्छेद 351:** क्षेत्रीय भाषाई पहचान का सम्मान करते हुए और भारत की "साझा संस्कृति" को ध्यान में रखते हुए केंद्र को हिंदी को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **RTE अधिनियम, 2009:** स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए।



### 2. सामाजिक-आर्थिक आयाम: "संज्ञानात्मक लाभ" (Socio-Economic Dimension)

- **समावेशी विकास:** अपनी मातृभाषा में शिक्षा "भाषाई विभाजन" को कम करती है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी युवाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिलता है।
- **मानव पूंजी:** शोध बताते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा बेहतर तार्किक सोच को बढ़ावा देती है, जिससे भविष्य में अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल तैयार होता है।
- **संज्ञानात्मक न्याय:** यह स्वीकार करता है कि स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों सहित सभी ज्ञान प्रणालियाँ राष्ट्रीय विकास के लिए मान्य और मूल्यवान हैं।



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

### 3. नैतिक और मानवाधिकार आयाम (Ethical & Human Rights Dimension)

- **गरिमा और पहचान:** किसी बच्चे को स्कूल में अपनी घरेलू भाषा छोड़ने के लिए मजबूर करना उसकी संस्कृति को "निम्न" मानने जैसा है, जिससे सांस्कृतिक अलगाव पैदा होता है।
- **समानता के ऊपर न्याय (Equity over Equality):** जहाँ "समानता" सभी को एक ही किताब देती है, वहीं "न्याय" हर बच्चे को उस भाषा में किताब देता है जिसे वह वास्तव में समझता है।

## नीतिगत ढांचा और डिजिटल सहायक (Policy Framework & Digital Enablers)

भारत अब भाषाई विविधता को एक चुनौती के बजाय एक शिक्षण संपत्ति के रूप में देख रहा है।

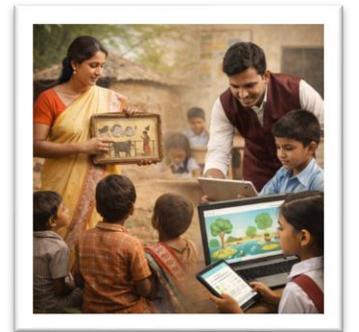
- **नीतिगत बदलाव (NEP 2020 और NCF 2022/23):** यह अनिवार्य करता है कि कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा होनी चाहिए।
- **तकनीकी हस्तक्षेप:**
  - **भाषिणी (BHASHINI):** एक AI-आधारित अनुवाद मंच जो भाषा की बाधाओं को तोड़ रहा है।
  - **दीक्षा (DIKSHA):** शिक्षकों के लिए बहुभाषी डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
  - **पीएम ई-विद्या और आदि वाणी:** स्थानीय बोलियों में सामग्री के साथ दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक पहुँच बनाना।

## प्रमुख चुनौतियाँ और मुद्दे (Key Challenges & Issues)

- इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले भारत को कई ढांचागत बाधाओं को दूर करना होगा:
- **शिक्षकों की कमी:** अधिकांश शिक्षक अंग्रेजी या मानक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षित हैं, न कि बहुभाषी शिक्षण पद्धति में।
- **"अंग्रेजी का विरोधाभास":** सामाजिक प्रतिष्ठा और वैश्विक नौकरियों के कारण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए माता-पिता का अत्यधिक दबाव।
- **संसाधनों की कमी:** गैर-अनुसूचित या आदिवासी बोलियों में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और साहित्य का अभाव।
- **मूल्यांकन बाधाएं:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं काफी हद तक एकभाषी हैं, जो मातृभाषा में सीखने वालों के लिए एक "कांच की छत" (बाधा) पैदा करती हैं।

## सफलता की कहानियाँ: राज्यों से सबक (Success Stories)

- **ओडिशा मॉडल:** 21 आदिवासी भाषाओं को कवर करने वाला एक अग्रणी कार्यक्रम, जिसने स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करके लगभग 90,000 बच्चों को लाभ पहुँचाया।
- **तेलंगाना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे, बहुभाषी संसाधन प्रदान करने हेतु डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना।



## आगे की राह: "भाषा मैटर्स" के सुझाव (The Way Forward)

- **बहुभाषी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन:** मंत्रालयों और तकनीकी भागीदारों के प्रयासों को एक साथ लाना।
- **शिक्षक सशक्तिकरण:** बहुभाषी शिक्षण कौशल को शामिल करने के लिए शिक्षकों के शुरुआती और बाद के प्रशिक्षण (B.Ed) में सुधार करना।
- **समावेशी मूल्यांकन:** ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना जो बच्चों को अपनी मातृभाषा में ज्ञान व्यक्त करने की अनुमति दे।
- **सामुदायिक भागीदारी:** पहचान और गौरव की भावना पैदा करने के लिए स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करना।

IAS-PCS Institute

## निष्कर्ष (Conclusion)

मातृभाषा में शिक्षा केवल एक शिक्षण उपकरण नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो समानता और सामाजिक एकजुटता सुनिश्चित करता है। "भाषा" को अपनाकर, भारत अपनी कक्षाओं को ऐसे समावेशी स्थानों में बदल सकता है जहाँ हर बच्चे की पहचान सीखने में बाधा नहीं, बल्कि एक सेतु बने।

## प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Questions)

Q1. हाल ही में चर्चा में रही 'भाषिणी' (BHASHINI) पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक AI-आधारित भाषा अनुवाद मंच है जिसका उद्देश्य शासन और शिक्षा में भाषा की बाधाओं को तोड़ना है।
2. इसका लक्ष्य क्लाउडसोर्स डेटा का उपयोग करके क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है।
3. यह लुप्तप्राय आदिवासी लिपियों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

Q2. भारतीय संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर भाषाओं के निर्देश से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 350A
2. अनुच्छेद 351
3. अनुच्छेद 29
4. अनुच्छेद 343

IAS-PCS Institute

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3, और 4

सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

प्रश्न: "भाषा केवल निर्देश का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और संज्ञानात्मक विकास का एक भंडार है।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (MTB-MLE) के महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन में संरचनात्मक चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द | 15 अंक)



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

**OPTIONAL SUBJECT**  
**वैकल्पिक विषय**  
**PSIR**  
Fee - मात्र 6999 ₹  
केवल 01 से 06 जुलाई  
Dr. Faiyaz Sir

**(वैकल्पिक विषय) Optional Subject**  
**GEOGRAPHY**  
**OPTIONAL**  
Fee - मात्र 6499 ₹  
केवल 21 से 26 जून